

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य

25/2014 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या:-25/2014(रे0वाद)

दायर दिनांक:- 17/03/2014

निर्णय दिनांक:-26/11/2025

अनवान

1. सकी देवी बेवा लालसिंह जाति रावत निवासी पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

---वादी

बनाम

1. भंवरसिंह पिता गंगासिंह जाति रावत निवसी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. पीस्ता ना0बा0 चंचल ना0बा0 पिता अर्जुनसिंह संरक्षक, दादी मूली बाई जाति रावत निवासी भूरी काकर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. मुली बाई बेवा गंगासिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
4. रणजीतसिंह पिता छोगासिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
5. फतेहसिंह पिता छोगासिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
6. प्रेमसिंह पिता छोगासिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
7. केली बेवा छोगासिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
8. भानसिंह पिता नेनसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
9. नेनुसिंह पिता नेतसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
10. प्रकाशसिंह पिता किशनसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
11. कुशालसिंह पिता धर्मसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य
25/2014 (रोवाद)
निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

12. जसवन्तसिंह पिता धर्मसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
13. नरेन्द्रसिंह पिता धर्मसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
14. सरोजदेवी बेवा धर्मसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
15. लक्ष्मणसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
16. तेजसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
17. नरपतसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
18. गोपालसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
19. नारायणसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
20. रामु बेवा पूनमसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
21. करमसिंह पिता भीमा जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
22. मोहनसिंह पिता भीमा जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
23. कैलाश पिता भीमा जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
24. पुरी बेवा भीमा जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
25. गणपतसिंह पिता राम जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
26. भगवानसिंह पिता रामा जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।
27. धापु बेवा राम जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।



७३
सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला राजसमन्द

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य
25/2014 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

28. कल्याणसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
29. भुरसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
30. रतनसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
31. नारायणसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
32. गिरधारीसिंह पिता लालसिंह जाति रावत निवासी भूरी काकर, पीली का चौडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ ।

---प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री नरेश जोशी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से - श्री ईन्द्रमल कंसारा , अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 15,16,
19, 20 एवं 27 ।

---निर्णय:-

आज यह पत्रावली प्रार्थना-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृत्तान्त इस प्रकार है कि वादिया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-53 के तहत हाजा न्यायालय में वाद संख्या 25/2014 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीली का चौडा, पटवार मण्डल ताल, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द अवस्थित आराजी वादिया व प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी हैं। उक्त संयुक्त आराजी पर विधिवत् हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 28 से 32 के नाम अलग से खाता खोले जाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन-वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा द्वारा प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के अन्तर्गत



20
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य
25/2014 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

प्रार्थना प्रस्तुत कर वादपत्र पर कार्यवाही स्थगित करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया कि- वादीया श्रीमति सकी देवी द्वारा माननीय न्यायालय आप में एक वाद बाबत बटवारा दिनांक 23.05.2014 को प्रस्तुत किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 25/14 दर्ज होकर मुझ प्रतिवादी को उक्त वाद की जानकारी जरीये सुचना पत्र लोक अदालत केम्प कोर्ट ताल की दिनांक 01.06.2017 को हुई। वादीया श्रीमति सकी देवी ने ग्राम पीली का बोडा पटवार हल्का ताल तह० देवगढ़ के खाता सं० 83/15 खसरा नं० 1572/673 रकबा 13 बीघा 9 विस्वा एवं खसरा नं० 1596/692 रकबा 35 बीघा 18 विश्वा कुल किता 2 रकबा 49 बीघा 7 विस्वा भूमि में अपने हिस्सेअनुसार बंटवारा हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण लक्ष्मणसिंह आदि द्वारा एक वाद माननीय न्यायालय आप में उक्त वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व रिकोर्ड मे गलत रूप से दर्ज हिस्से को दुरस्त कराने की घोषणा एवं खातेदार सही घोषित किया जाकर एवं उक्त वाद की बादीया सकी देवी का मुल खाते में गलत रूप से दर्ज 1/3 हिस्सा हटाया जाने की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो लक्ष्मणसिंह द्वारा माननीय न्यायालय आप में अक्टुम्बर 2012 में प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण सं० 17/13 होकर अनवान श्री लक्ष्मणसिंह पिता पुनम सिंह के नाम का होकर न्यायालय आप में विचाराधीन है। मुल बाद श्री लक्ष्मणसिंह द्वारा घोषणा का प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में जवाब में चल रहा है एवं उक्त वादग्रस्त आराजियात का ही प्रकरण वादीया द्वारा बटवारा का प्रस्तुत किया गया है। जब मुल घोषणा का वाद विचाराधीन है तब तक उक्त वादीया का बटवारा का वाद माननीय न्यायालय आप में चलने योग्य नहीं है इसलिये उक्त वाद अन्तर्गत धारा 10 सी० पी० सी० के तहत रोका जाना आवश्यक है जब तक मुल वाद घोषणा का आदेशित नहीं हो जाता तब तक उक्त वाद बटवारा का चलने योग्य नहीं है एवं पश्चातवर्ती वाद को रोका जाना कानुनन आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सं० 25/14 का निस्तारण पुर्ववर्ती वाद जो प्रतिवादी ने प्रस्तुत कर रखा है प्र० सं० 17/13 के



ॐ
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्व

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य
25/2014 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

निस्तारण तक रोका जाये। एवं पश्चातवर्ती वाद को मुल वाद जो वादी द्वारा बंटवारा का प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद को पूर्ववर्ती वाद के शामिल तब तक कर दिया जाये।

अधिवक्ता वादिया ने सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में एक वाद सकी देवी द्वारा पेश किया जाना स्वीकार है, शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थना-पत्र की कलम संख्या 02 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 स्वीकार है प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 गलत होकर अस्वीकार है यह कहना गलत है कि उक्त वाद चलने योग्य नहीं है यह भी अस्वीकार है कि उक्त वाद धारा 10 सीपीसी के तहत रोका जा सकता है। अतः अंत में अंकित प्रार्थना गलत होकर अस्वीकार है प्रतिवादीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है। अधिवक्ता वादिया ने अपने विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि दोनो वादों में सम्पूर्ण पक्षकार समान नहीं है साथ ही विवाद, विषय, विवाधक, रिलीफ भी समान नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है।

Provision

प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में वादपत्र में संशोधन हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है:-

10. Stay of suit.—

No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim



20
सहायक कलेक्टर
बhopal, जिला राजसमन्द

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य

25/2014 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court.

Explanation.—The pendency of a suit in a foreign Court does not preclude the Courts in India from trying a suit founded on the same cause of action.

Interpretation

1. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के प्रावधान की माननीय न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा सिविल अपील 2908/2013 उनवान *Aspi Jal And Anr vs Khushroo Rustom Dadyburjor* में दिनांक 05.04.2013 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के प्रावधान की विस्तृत व्याख्या (Interpretation) की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

From a plain reading of the aforesaid provision, it is evident that where a suit is instituted in a Court to which provisions of the Code apply, it shall not proceed with the trial of another suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties. For application of the provisions of Section 10 of the Code, it is further required that the Court in which the previous suit is pending is competent to grant the relief claimed. The use of negative expression in Section 10, i.e. "no court shall proceed with the trial of any suit" makes the provision mandatory and the Court in which the subsequent suit has been filed is prohibited from proceeding with the trial of that suit if the conditions laid down in Section 10 of the Code are satisfied. The basic purpose and the underlying object of Section 10 of the Code is to prevent the Courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigations in respect of same cause of action, same subject matter and the same relief. This is to pin down the plaintiff to one litigation so as to avoid the possibility of contradictory verdicts by two courts in respect of the same relief and is aimed to protect the defendant from multiplicity of proceeding.



20/10
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्ध

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य

25/2014 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

2. उक्त विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टान्तों द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के निम्न मुख्य उद्देश्य (Basic objects) प्रतीत होते हैं-

1. समान विवाद एवं समान प्रकरण वाले दो या अधिक समानांतर वादपत्र पर समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को समानांतर विचारण करने से रोकना।
2. समान विवाद एवं समान प्रकरण वाले दो या अधिक समानांतर वादपत्र पर समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को परस्पर विरोधी निष्कर्ष वाले निर्णय करने से रोकना।

Role/Power of Court

3. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के प्रावधान के अनुप्रयोजन में न्यायालय की भूमिका, शक्तियां व दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 2082/1998 उनवान **Pukhraj D. Jain & Ors vs G. Gopalakrishna** में दिनांक 16.04.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के तहत न्यायालय की भूमिका एवं शक्तियों (Role/Power of Court) को स्पष्ट करते हुए निम्न दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

8. *The proceedings in the trial of a suit have to be conducted in accordance with provisions of the Code of Civil Procedure. Section 10 CPC no doubt lays down that no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India having jurisdiction to grant the relief claimed. However, mere filing of an application under section 10 CPC does not in any manner put an embargo on the power of the court to examine the merits of the matter. The object of the section is to prevent Courts of concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suits in respect of the same matter in issue. The section enacts merely a rule of procedure and a*



ms
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्व

सकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य
25/2014 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

decree passed in contravention thereof is not a nullity. It is not for a litigant to dictate to the court as to how the proceedings should be conducted, it is for the court to decide what will be the best course to be adopted for expeditious disposal of the case. In a given case the stay of proceedings of later suit may be necessary in order to avoid multiplicity of proceedings and harassment of parties. However, where subsequently instituted suit can be decided on purely legal points without taking evidence, it is always open to the court to decide the relevant issues and not to keep the suit pending which has been instituted with an oblique motive and to cause harassment to the other side.

**Indian Bank V. Maharashtra State Coop.
Marketing Federation Ltd, AIR 1998 SC 1952**

—न्यायालय ने कहा कि यदि समान पक्षकारों एवं समान विषय पर वाद पूर्व में लम्बित है तो बाद का वाद स्थगित किया जाएगा।

**National Institute of Mental Health & Neuro Science V.
C. Parameshwara. (2005)2 SCC 256**


—न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 10 CPC का उद्देश्य एक ही विवाद पर दो अलग-अलग निर्णयों से बचना एवं Litigation की Multiplicity रोकना है।

प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र की तुलना निम्न प्रकार है:-

परीक्षण का आधार	पूर्ववर्ती वाद	पश्चात्वर्ती वाद
वाद का प्रकार	दावा	दावा
शीर्षक	समान	समान
पक्षकार	समान	समान
सम्पत्ति/आराजी	समान	समान
सक्षम न्यायालय	हाजा न्यायालय	हाजा न्यायालय
विषय-वस्तु	घोषणा हेतु दावा	विभाजन

4. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मूलतः एवं सारतः वाले पूर्ववर्ती वाद के सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए समान पक्षकारों के मध्य समान विषय-वस्तु को लेकर पश्चात्वर्ती वाद के विचारण के न्यायालय को




सहायक कलेक्टर
देवाड़, जिला राजसमन्व

प्रतिबंधित किया गया है। उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है।

5. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र की तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पत्रावली व प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी व प्रतिवादी संयुक्त आराजी में सहकाशतकार हैं। उक्त वादग्रस्त पर वाद अन्तर्गत धारा 88-89-91 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण संख्या 17/2013 वाद विचाराधीन है। उक्त वादग्रस्त आराजियात के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण संख्या 25/2014 विचाराधीन है।
6. इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के तहत पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद में विवाद की मुख्य विषय वस्तु समान होने पर पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने के प्रावधान हैं। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय को पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद के वादी व प्रतिवादी के अभिकथनों को सारतः समझते हुए विवाद के मुख्य विषय वस्तु का चिन्हीकरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अगर किसी वाद में किसी पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों की चतुराई पूर्वक शब्दों के हेरफेर व चतुराईपूर्वक प्रारूपण किये जाने से भिन्न-भिन्न विषयवस्तु का छद्म प्रस्तुतीकरण किये जाने का प्रयास किया जाता है। उस स्थिति में न्यायालय की विशेष भूमिका की अपेक्षा की जाती है। साथ ही प्रक्रियात्मक कानून की तकनीकी खामियों से न्यायालय विवश ना होकर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का स्वतः प्रयोग लेकर किसी प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त विषयवस्तु के प्रभावी व समग्र निस्तारण हेतु न्यायालय आवश्यक कदम उठा सकता है। हस्तगत प्रकरण में पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

राकी देवी बनाम भंवरसिंह व अन्य
25/2014 (रे0वाद)

निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

के वादी व प्रतिवादी के अगिकथनों को सारतः सांग्रहिते हुए विवाद के मुख्य विषय वस्तु का चिन्हीकरण किये जाने के पश्चात् उक्त दोनों दावा के मध्य विषयवस्तु की समानता पाता है। अतः आदेश दिया जाता है कि-

प्रतिवादी का उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं हाजा न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 25/2014 में कार्यवाही स्थगित करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।



7/10/25
(मोहकम सिंह मिश्रा निम्नान्वार R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द